the earth-work is being washed out. May I know whether the Government will decide to complete the work of the raising of the level before the coming monsoon?

SHRI H. M. TRIVEDI: A portion of the National Highway No. 17 in Kolaba district is certainly not in a very good condition. So far as the portion between Sangameswar and Ratnagiri is concerned, the State Government have already framed an estimate which they have forwarded to the Central Government for work during 1974-75

SHRIMATI ROZA DESHPANDE: How many bridges are incomplete in this national highway in Maharashtra? Secondly may I know whether the bridges connecting Bombay with Cape Comorin have been completed or not?

SHRI H M TRIVEDI On National Highway No 17, three major bridges lying one each in Goa, Karnataka and Kerala State are already under construction and one in Goa is under investigation

SHRI P R SHENOY May I know whether it is a fact that National Highway No 17 is not straight and is circuitous at several places and representations are being made to the Government to straighten this road, particularly between Kanhanged-Kasargode in Kerala State

SHRI H M TRIVEDI The re-alignment of the road has been proposed in Kerala but that re-alignment has not yet been approved or sanctioned

Japanese Interest in Steel Projects in India

+

*536. SHRI NAWAL KISHORE SHARMA

SHRI C K CHANDRAPPAN·

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state

(a) whether the visiting Japanese delegation have shown interest in setting up steel projects in India;

(b) if so, the locations of steel projects, together with the annual production, capacity and the cost;

(c) the extent to which the domestic and export requirements of steel would be met after the projects start production; and

(d) the expected foreign exchange to be earned as a result thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SUKHDEV PRASAD): (a) No, Sir

(b) to (d) Do not arise.

श्री नवल किशोर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने नकारात्मक जवाब दिया है। मैं जानना चहूंगा कि हम जापान को आयरन और एक्सपोर्ट करते हैं और बावजूद इसके कि हमारे देश मे स्टील का एक्सपेंशन हुआ है, इम्पोर्ट भी करते है। ऐसी स्थिति मे क्या वजह थी कि हमने जापानी डेलीगेशन से हमारे यहा स्टील के प्रोडक्शन के लिये कारखाने लगाने पर चर्चा नही की। इसकी कोई खास वजह थी क्या ?

अध्यक्ष महोदय प्रश्न कुछ और था और अब आप चर्चा की तरफ चल पडे।

इस्पात और खानमंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) श्रीमन, जो हमारी आवश्यकता है इस्पात की उसको देखते हुये पाचवी योजना के अन्त तक जो हमारे मौजूदा कारखाने हैं उनमे विस्तार की योजना भिलाई मे है, बोकारो मे नया कारखाना बन रहा है, और यह काम चल रहा है। दूसरे जो तीन कारखाने दक्षिण भारत मे बनाने का प्रश्न है

अध्यक्ष महोदय : आपने कुछ चर्चा की है डेलीगेशन मे ओर लगाना है कि नही इसका जवाब दें।

श्री चन्द्र जीत यादव . अभी आवश्यकता देखते हुये कोई नया कारखाना लगाने की

जरूरत नहीं है इसलिये जापान के न किसी ने हमसे विधिवत कहा है और न हम विचार कर रहे हैं।

SHRI C. K. CHANDRAPPAN: I would like to know from the hon. Minister whether it is a fact that a Japanese team of industrialists had visited this country and held talks with the Government of India in Jaipur recently and, in these discussions, whether it is a fact that the Japanese team said that they are ready to collaborate with India to set up various projects including mini-steel mills considering the fact that Japan wants to save labour whereas we in our country want labour-intensive schemes.

All these factors were taken into account and they suggested that they are ready to help technologically and even financially our country to set up mini-steel mills along with many other projects. I want to know about that.

SHRI CHANDRAJIT YADAV: It is a fact that the Japanese Trade delegation visited Jaipur this year. It was a non-official delegation. They participated in a conference held at Jaipur. But they did not put up any proposals specifically for mini-steel mills. As I said earlier, there is no specific proposal from the Government of Japan. Sometimes, the Japanese business houses, some consultants, have shown some interest. But there is no specific proposal.

SHRI M. S. SANJEEVI RAO: I would like to know from the hon Minister whether he is considering to approach Japan for setting up palletisation mills like the one set up by Mr. Chogle in Goa so that we can export iron pellets instead of iron ore, thereby saving not only freight rates but also foreign exchange.

SHRI CHANDRAJIT YADAV: It is a fact that, instead of exporting iron ore and fines, if we are in a position to export pellets, that will be more beneficial. That is a new process. There are one or two pellet plants now in our country. We are having negotiations and we are proposing to have more pellet plants in our country. There is no question of collaboration with any other country. The knowhow is available in this country. The question is only of finances and as soon as they are available, we will try to have more pellet plants.

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : मंत्री जी ने ना मे जवाब दिया है ; मैं जानना चाहता हूं कि जापानी डेलीगेशन जो भारत में आया इसने क्या कुछ टाटा आयरन स्टील कम्पनी के एक्सपेंशन के बारे मे कहा है, और निपन स्टील कोरपोरेशन आफ जापान ने जो बातचीत की थी क्या उसमें कोई इस बारे मे सवाल पैदा हुआ था ?

श्री चन्द्रजीत यादव : जहा तक मैने नही मे जवाब दिया है वास्तविकता वही है। जहां तक टाटा का सवाल है टिस्को ने अपने एक्सपेंशन का एक प्रोपोजल प्रस्तुत किया था और जापान की निपन स्टील कोरपोरेशन को कंसल्टेंटस की मदद से उन्होने एक डिटेल्ड फीजेबिलिटी रिपोर्ट तैयार की है दो मिलियन टन इगट्स और बढ़ाने की। अब वह टिस्को और उनके बीच मे है, उसमे सरकार कहीं नही आती है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : जापान सरकार के प्रतिनिधि मंडल और व्यापारियो से बात कर के आपके भूतपूर्व मंत्री जी ने घोषणा कि थी कि हम देश के अन्दर एक हजार मिनी स्टील प्लाट लगाने जा रहे है। क्या यह बात सही है ?

यदि नही, तो किस आधार पर उन्होने वह घोषणा की थी और मिनी स्टील प्लाट कहा लगेंगे ? इस समय जो भारी मात्रा मे इस्पात जमा हो गया है इसको बेचने के बारे मे कोई चर्चा की है ?

श्री चन्द्र जीत यादव : मैंने पहले भी कहा है कि मिनी स्टील प्लाट लगाने के बारे मे जापान से बातचीत का प्रश्न ही नही पैदा हुआ है । जहा तक एक हजार मिनी स्टील प्लाट लगाने की घोषणा की थी वह मत्री महोदय का अपना निजी विचार था और वह समझते थे कि इसकी सभावना है । उस पर हम भी विचार कर रहे हैं, देखेंगे जैसी सभावना होगी विचार करेंगे ।

SHRI R V SWAMINATHAN While answering a supplementary question, the Minister has mentioned that some steel mills are coming up in South India Particularly in the Salem steel mill, no work is being done, it has been slowed down or it has been stopped I want to know what is the present position about the Salem steel plant

SHRI CHANDRAJIT YADAV: I have made it very clear time and again that it is wrong to say that the work has been stopped at Salem. Some work has already been taken up and it has been completed. In this financial year, for the money which is required for this year, we are making all possible arrangements, so that the work is in progress and does not stop.

श्री सरजू पांडे : अध्यक्ष जी, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश मे चर्चा चली है और मिनी स्टील प्लांट की स्थापना की बात चली थी कई लोगो ने प्रार्थना पत्र सरकार को दे रखें है, कि मिनी स्टील प्लान्ट लगाने के लिये इजाजत दी जाय । तो मैं जानना चाहता हू कि इस तरह के कितने प्रार्थना पत्र आये और उस पर क्या विचार हो रहा है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : मिनी स्टील प्लांट लगाने से हमने कभी नहीं रोका है । यहां उत्तर दिया जा चुका है । कि पिछले साल 118 मिनी स्टील प्लाट लगाने के लिये लाइसेंस दिये गये थे । एक स्टेज पर हमने कोई प्रतिबध नही लगाया था । लाइसेंस की व्यवस्था उठा ली थी । लेकिन स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश मे बिजली के अभाव मे आज 17 कारखाने बन्द है और छ आदमियो ने जिन्होने लाइसेंस लिये थे उन्होने अपने लाइसेंस वापिस कर दिये हैं । आगे तभी विचार कर सकते है जब बिजली उपलब्ध हो और इनको बिजली लगातार मिलती रहे इसके बिना वे चल नही सकते हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मत्री महोदय ने कहा है कि बिजली की कमी की वजह से उत्तर प्रदेश मे कारखाने बन्द हैं । और जिनको लाइसेंस दिये गये थे वे उनको वापिस कर रहे हैं । झासी का एक कारखाना स्वय अपनी बिजली पैदा करना चाहता था लेकिन सरकार ने स्टील प्लांट लगाने का लाइसेंस तो दे दिया लेकिन बिजली पैदा करने का नही दिया । मैं जानना चाहता हू कि सरकार और लोगो को भी बिजली पैदा करने की इजाजत देने पर विचार कर रही है या केवल सरकार ही यह काम करेगी ।

श्री चन्द्रजीत यादव : अगर माननीय सदस्य झासी वाले कारखाने की पूरी डिटेल्स मुझे दे तो मैं इसको देखूगा । मैं समझता हू कि अगर उसमे इम्पोर्ट वगैरह का कोई प्रश्न नही है तो उस पर प्रतिबध नही होना चाहिए । मुझे वह डिटेल्ज भेज दें तो मैं देख लूगा ।

SHRI B V NAIK May I know from the hon Minister whether the Finance Minister of the Government of Karnataka has gone on record saying that the Government of Karnataka would be interested in collaboration with a Japanese firm or firms in seeing that the proposed Vijayanagar Steel Plant is made to take off and completed within a year and whether any concrete proposals have been received by the hon Minister and if so, what is his reaction?

MR. SPEAKER. I am sorry Members are asking specific questions without notice If the Minister has any information, he can give Otherwise, he is not bound to give it.

SHRI CHANDRAJIT YADAV I have no informations.

MR. SPEAKER: Shri M. C Daga—not here

Shri Ramsahay Pandey.

Faults in Working of Wage Law

+

*538. SHRI R S. PANDEY

SHRI YAMUNA PRASAD MANDAL:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in a local daily dated the 20th November, 1974 regarding 'Faults seen in working of Wage Law'; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI BALGOVIND VERMA). (a). A report on the subject which appeared in the Indian Express dated 20th November, 1974 has been seen by Government

(b) The report refers mainly to delays in the revision of wages notified under the Minimum Wages Act, 1948 and deficiencies in their enforcement The State Governments had been advised from time to time to take care of both these aspects

श्री राम सहाय पांडे : राष्ट्रीय वेतन कमिशन ने क्या न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन के बारे मे भी कोई सिफारिश की थी और अगर की थी तो वह क्या है ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : उसने नेशनल मिनिमम वेज पर विचार किया था और लोगों के विचारो को सुना भी था। वह इस निष्कर्ष पर पहुचा कि चूकि मुल्क बहुत बडा है और देश मे जगह जगह पर एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त, एक रिजन से दूसरे रिजन मे डिवेलेपमेंट के मामले मे डिफेमिस है इसलिए नेशनल मिनिमम वेज पासिबल नही है, मुम्किन नही है। उसने जो कहा था वह मै आपको बताता हू

National minimum wage in the sense of uniform minimum monetary rate of remuneration for the country as a whole is neither feasible nor desirable It may be possible however that in the different homogenous regions in each State a regional minimum wage could be notified. An effort should be made to fix such regional minimum

श्री राम सहाय पांडे : मै मत्री महोदय के वक्तव्य से सहमत हू। एक रिजन से दूसरे रिजन मे और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से आर्थिक स्थिति से अन्तर है। लेकिन एक केन्द्रीय सस्था आपने बनाई है जिस का काम और दायित्व यह है कि न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन का कोई क्रम तमाम परिस्थितियो को देखते हुए रिजन वाइज या प्रान्त वाइज बना दे। परिस्थितियो को देखते हुए, एक रिजन और दूसरे रिजन मे फर्क को देखते हुए क्या इस के सम्बन्ध मे कुछ किया नही जा सकता है और नही किया जा सकता है तो उसका कारण क्या है ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : नेशनल मिनिमम वेज निश्चित करना केन्द्रीय सरकार के हाथ से नही है। यह राज्य सरकारो के अन्तर्गत काम ज्यादातर आता है एम्प्लायमेंट ज्यादा तर राज्य सरकारो के अन्तर्गत आता है। बहुत थोडे से मामलात मे ही हम आते है।

श्री राम सहाय पांडे : मार्गदर्शन तो आप कर ही सकते है।

श्री बालगोविंद वर्मा : मार्गदर्शन तो हम करते रहते है। मिसाल के तौर पर आप बीडी इडस्ट्री को ले। स्टेट गवर्नमेंट के लेबर मिनिस्टर को हमने बुलाया और दूसरे सम्बन्धित लोगो को बुलाया, उनको